Panel discussion on Digital Agriculture Management – Feb 18, 2021

Morning India
www.sanmarglive.com
Ranchi, Friday
19 February 2021

Panel discussion on Digital Agriculture Management conducted at ICFAI University

A panel discussion on "Digital Agriculture Management - Opportunities and Challenges" was conducted at ICFAI University. The panel discussion was moderated by Prof O R S Rao, Vice-Chancellor of the ICFAI University.

Welcoming the participants to the panel discussion, Prof O R S Rao, Vice-Chancellor of the University said, "In the last few years, India achieved self-sufficiency in food grains production and is also able to export the same. Our Government, under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi launched a lot of initiatives like setting up 10,000 Farmers Producer Organisations (FPOs) and electronic National Agriculture Market (e-NAM) to enhance the incomes of the farmers. However, better deployment of Emerging Technologies like Artificial Intelligence, IOT, Satellite Image Processing can help in further improving their incomes. Objective of today's discussion is to identify such opportunities and challenges in implementation of the same.

Dr D K Srivastava highlighted the need for sustainable agriculture, wherein Air, water and food security are to be conserved. He also explained the steps taken by the Government to boost Agriculture and Forests. The concepts of precision farming and linking Satellite Imagery to the Agriculture have created the large data base of inputs, which can be used for Crop Selection, Harvesting etc so as to increase the yield and productivity.

Sri Pradeep Hazari exhorted the need for introducing easy-to-use technologies like Mobile apps, hand held devices technology in farming. He also explained how digital technology can help in improving the linkage between producers and markets so as to increase the price realizations. He also suggested that Market Models of Dairy Farming may be studied to identify their good practices in agricultural farming. He also highlighted the need for up-skilling and reskilling the current employees in agri-related organizations like Farm extensions, Agri-input providers, agri-financing, retailing, government etc so that Digital Transformation of agri-management can be effectively implemented.

Responding to this suggestion, Prof O R S Rao informed that the University is launching a 2 month certificate program in digital agriculture Management in order to up-skill and reskill employees. "The program will commence on March 7, 2021 and last date for applications is 28th Feb 2021. More details can be obtained from the University's website", Prof Rao added.

Prof Kaushal Kumar Sinha appreciated the initiative of the University to offer the Certificate program, which can help the working professionals in the agri-related organizations to build and enhance their careers.

सन्मार्ग
रांची, शुक्रवार 19 फरवरी 2021
04

इक्फाई विवि में डिजिटल कृषि प्रबंधन पर पैनल चर्चा, बोले कुलपति

भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर

संवाददाता

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड में डिजिटल कृषि प्रबंधन-अवसर और चुनौतियां पर गुरुवार को पैनल चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जहां भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की, वहीं इसे निर्यात करने में भी सक्षम है। सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) स्थापित करने जैसी कई पहल की है। प्रो राव ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अप-स्किल और री-स्किल के लिए डिजिटल कृषि प्रबंधन में 2 माह का प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू कर रहा है। कार्यक्रम 7 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ डीके श्रीवास्तव ने कहा कि वायु, जल और खाद्य सुरक्षा को संरक्षित किया जाना है। उन्होंने कृषि और वन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा की सटीक खेती की अवधारणाओं और सैटेलाइट इमेजरी को कृषि से जोड़ने के लिए इनपुट का बड़ा डेटा बेस बनाया गया है। जिसका उपयोग फसल चयन, कटाई आदि के लिए किया जा सकता है। कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी ने खेती में मोबाइल एप्लिकेशन, हाथ से संचालित उपकरणों की तकनीक जैसी आसान तकनीकों को पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक उत्पादकों और बाजारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। नाबार्ड के पूर्व सीजीएम प्रो कौशल कुमार सिन्हा ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की।

इक्फाई विवि में डिजिटल कृषि प्रबंधन पर पैनल चर्चा आयोजित

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड में डिजिटल कृषि प्रबंधन – अवसर और चुनौतियां पर एक पैनल चर्चा की गई। इस पैनल चर्चा में डॉ। डीके श्रीवास्तव (आईएफएस), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड सरकार के प्रधान संरक्षक, प्रदीप हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि विभाग, पशुपालन और सहकारिता, झारखंड सरकार और कौशल कुमार सिन्हा, पूर्व सीजीएम, नाबार्ड के लोग शामिल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओ आर एस राव ने प्रतिभागियों को पैनल चर्चा में स्वागत करते हुए कहा की पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की और वही इसे निर्यात करने में भी सक्षम है। सरकार, हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) स्थापित करने जैसी कई पहल की है। हालांकि, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग की बेहतर तैनाती से किसानों की आय को और बेहतर बना ने में मदद मिल सकती है। आज की पैनल चर्चा का उद्देश्य इसी तरह के टेक्नोलॉजीज के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना है। पैनल चर्चा को संबोधित करते हुये डॉ। डी के श्रीवास्तव ने दीर्घकालिक कृषि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें वायु, जल और खाद्य सुरक्षा को संरक्षित किया जाना है। उन्होंने कृषि और वन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होने कहा की सटीक खेती की अवधारणाओं और सैटेलाइट इमेजरी को कृषि से जोड़ने के लिए इनपुट का बड़ा डेटा बेस बनाया गया है, जिसका उपयोग फसल चयन, कटाई आदि के लिए किया जा सकता है ताकि उपज और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। प्रदीप हजारी ने खेती में मोबाइल एप्लिकेशन, हाथ से संचालित उपकरणों की तकनीक जैसी आसान तकनीकों को पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रांची, रविवार
21.02.2021
खबर मन्त्र 03

इक्फाई विश्वविद्यालय में डिजिटल कृषि प्रबंधन पर पैनल डिस्कशन

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड में डिजिटल कृषि प्रबंधन-अवसर और चुनौतियां पर एक पैनल चर्चा की गई। इसमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ डीके श्रीवास्तव (आईएफएस) कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी और नाबार्ड के पूर्व सीजीएम कौशल कुमार सिन्हा शामिल थे। विवि के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने प्रतिभागियों को पैनल चर्चा में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है और वही इसे निर्यात करने में भी सक्षम है। सरकार हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) स्थापित करने जैसी कई पहल की है। हालांकि, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग की बेहतर तैनाती से किसानों की आय को और बेहतर बना ने में मदद मिल सकती है। आज की पैनल चर्चा का उद्देश्य इसी तरह के टेक्नोलॉजीज के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना है। पैनल चर्चा को

संबोधित करते हुए डॉ डी के श्रीवास्तव ने दीर्घकालिक कृषि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें वायु, जल और खाद्य सुरक्षा को संरक्षित किया जाना है। उन्होंने कृषि और वन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा की सटीक खेती की अवधारणाओं और सैटेलाइट इमेजरी को कृषि से जोड़ने के लिए इनपुट का बड़ा डेटा बेस बनाया गया है, जिसका उपयोग फसल चयन, कटाई आदि के लिए किया जा सकता है ताकि उपज और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। वहीं, श्री प्रदीप हजारी ने खेती में मोबाइल एप्लिकेशन, हाथ से संचालित उपकरणों की तकनीक जैसी आसान तकनीकों को पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक उत्पादकों और बाजारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है ताकि मूल्य की वास्तविकताओं को बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डेयरी फार्मिंग के मार्केट मॉडल का अध्ययन, कृषि खेती में उनकी अच्छी तरीको की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कृषि-संबंधित संगठनों जैसे कृषि विस्तार, कृषि-इनपुट प्रदाताओं, कृषि-वित्तपोषण, खुदरा बिक्री, सरकार आदि में वर्तमान कर्मचारियों की अप-स्किलिंग और री-स्किल्लिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि कृषि-प्रबंधन के डिजिटल परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सुझाव का जवाब देते हुए प्रो ओआर एस राव ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अपस्किल और री-स्किल के लिए डिजिटल कृषि प्रबंधन में 2 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू कर रहा है। कार्यक्रम 7 मार्च 2021 को शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 है। प्रो राव ने कहा की अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। प्रो कौशल कुमार सिन्हा ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम को पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की, जो कृषि से जुड़े संगठनों में काम करने वाले पेशेवरों को अपने करियर बनाने और बढ़ाने में मदद कर सकता है।

www.ajhindidaily.in
रांची, २१ फरवरी, २०२१
आज
४

दीर्घकालिक कृषि की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाये : श्रीवास्तव

डिजिटल तकनीक उत्पादकों और बाजारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है : प्रदीप हजारी

इक्फाई विश्वविद्यालय में डिजिटल कृषि प्रबंधन-अवसर और चुनौतियां पर पैनल चर्चा का आयोजन

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड में 'डिजिटल कृषि प्रबंधन-अवसर और चुनौतियां' पर एक पैनल चर्चा की गई। इस पैनल चर्चा में डा. डीके श्रीवास्तव (आईएफएस), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड सरकार के प्रधान संरक्षक, प्रदीप हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि विभाग, पशुपालन और सहकारिता, झारखंड सरकार और कौशल कुमार सिन्हा, पूर्व सीजीएम, नाबार्ड के लोग शामिल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ओआरएस.राव ने प्रतिभागियों को पैनल चर्चा में स्वागत करते हुए कहा की पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की और वही इसे निर्यात करने में भी सक्षम है। सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) स्थापित करने जैसी कई पहल की है। हालांकि, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग की बेहतर तैनाती से किसानों की आय को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आज की पैनल चर्चा का उद्देश्य इसी तरह के टेक्नोलॉजीज के कार्यान्वयन में अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना है। पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए डा. डीके श्रीवास्तव ने दीर्घकालिक कृषि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें वायु, जल और खाद्य सुरक्षा को संरक्षित किया जाना है। उन्होंने कृषि और वन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा की सटीक खेती की अवधारणाओं और सैटेलाइट इमेजरी को कृषि से जोड़ने के लिए इनपुट का बड़ा डेटा बेस बनाया गया है, जिसका उपयोग फसल चयन, कटाई आदि के लिए किया जा सकता है ताकि उपज और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। प्रदीप हजारी ने खेती में मोबाइल एप्लिकेशन, हाथ से संचालित उपकरणों की तकनीक जैसी आसान तकनीकों को पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक उत्पादकों और बाजारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है ताकि मूल्य की वास्तविकताओं को बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डेयरी फार्मिंग के मार्केट मॉडल का अध्ययन, कृषि खेती में उनकी अच्छी तरीकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कृषि-संबंधित संगठनों जैसे कृषि विस्तार, कृषि-इनपुट प्रदाताओं, कृषि-वित्त पोषण, खुदरा बिक्री, सरकार आदि में वर्तमान कर्मचारियों की अप-स्किलिंग और री-स्किल्लिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि कृषि-प्रबंधन के डिजिटल परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सुझाव का जवाब देते हुए, प्रोफेसर ओआरएस.राव ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अपस्किल और री-स्किलल के लिए डिजिटल कृषि प्रबंधन में 2 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू कर रहा है। कार्यक्रम 7 मार्च को शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 है। प्रो.राव ने कहा की अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर कौशल कुमार सिन्हा ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की, जो कृषि से जुड़े संगठनों में काम करने वाले पेशेवरों को अपने करियर बनाने और बढ़ाने में मदद कर सकता है।